

न्यायपालिका का भारतीयकरण

प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अखलि भारतीय न्यायक सेवा (AIJS) ।

मेन्स के लयः

भारत में न्यायपालिका संबन्धी पहल, भारतीय न्यायक प्रणाली से संबन्धति चुनौतयँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑनलाइन ई-नरीक्षण सॉफ्टवेयर के उद्घाटन के दौरान [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) ने कहा कि [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा दयि गए नरिणयों का अब चार भाषाओं- हदि, तमलि, गुजराती और ओडयि में अनुवाद कयि जाएगा ।

- इस पहल के परिणामस्वरूप न्यायपालिका का भारतीयकरण होगा जो कसिमय की मांग है ।

न्यायपालिका का भारतीयकरण:

- भारतीयकृत न्यायपालिका:
 - CJI के अनुसार, न्यायालयों को वादी-केंद्रति होने की आवश्यकता है, जबकि न्याय वतिरण का सरलीकरण प्रमुख चति होनी चाहयि ।
 - CJI ने नरिदषिट कयि क न्यायपालिका के भारतीयकरण का अर्थ न्याय वतिरण प्रणाली का स्थानीयकरण है ।
- भारत की सदयों पुरानी न्यायक प्रणाली:
 - भारत में वशि्व की सबसे पुरानी न्यायक प्रणाली है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है ।
 - ऐतहासक काल से ही भारत में एक बहुत ही प्रभावी, वशि्वसनीय और लोकतांत्रक न्यायक प्रणाली रही है, लेकिन वर्तमान नरिणयों में अधकिंश बयान/कथन पश्चमी न्यायशास्त्र से लयि गए हैं ।
 - न्याय प्रदान करने की भारत की अपनी प्राचीन प्रणाली को बहुत कम मान्यता दी जाती है ।
- संबन्धति अनुशंसार्ः
 - मलमिथ समति की रपिर्ट: मलमिथ समति (2000) ने सुझाव दयि कसिंहति की एक अनुसूची सभी कषेत्रीय भाषाओं में प्रकाशति की जानी चाहयि ताकि अभयिक्त अपने अधकिारों को जान सकें, साथ ही उन्हें कैसे लागू कयि जाए और उन अधकिारों के उल्लंघन होने पर कसिसे संपर्क कयि जाए ।
 - वधिआयोग, 1958: [अखलि भारतीय न्यायक सेवा \(AIJS\)](#) को पहली बार वर्ष 1958 में [वधिआयोग की 14वीं रपिर्ट](#) द्वारा प्रस्तावति कयि गया था ।
 - वधिआयोग की एक रपिर्ट (1987) में सफिरशि की गई थी कभारत में प्रतिदिस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश होने चाहयि, जबकि तब यह संख्या 10.50 थी ।

न्यायक प्रणाली में सुधार के लयि पहल:

- वीडयो कॉन्फरेंसगि (VC):
 - लॉकडाउन के दौरान वीडयो कॉन्फरेंसगि ही मुख्य सहारा रहा है ।
 - दल्लि [उच्च न्यायालय](#) एकमात्र ऐसा न्यायालय है जसिने VC के माध्यम से अधकितम मामलों की सुनवाई की है ।
- AI आधारति सुपेस (SUPACE) पोर्टल:
 - मई 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी शोध के साथ न्यायाधीशों की सहायता करने के उद्देश्य से [कतरमि बुद्धमितता \(Artificial Intelligence- AI\)](#) आधारति [सुपरीम कोर्ट पोर्टल फॉर अससिटेस इन कोर्ट एफशिर्सि](#) (Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency- SUPACE) लॉन्च कयि ।
- न्याय वतिरण और कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मशिन:

- मशिन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परसिमापन के लिये एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायापालिका की शक्ति में वृद्धि, नीति एवं वधायी उपायों सहित न्यायालयों के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचा शामिल है।
- ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों हेतु बुनियादी ढाँचे में सुधार:
 - बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये **केंद्र परायोजति योजना (Centrally Sponsored Scheme- CSS)** की शुरुआत के बाद से **9291.79 करोड़ रुपए** जारी किये गए हैं।
 - कोर्ट हॉल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) का लाभ उठाना:
 - सरकार ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम करने के लिये पूरे देश में **ई-कोर्ट मशिन मोड परियोजना** को लागू कर रही है।
 - कंप्यूटरीकृत ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ:

- **लंबित मामलों की बड़ी संख्या:** भारतीय न्यायालयों के समक्ष 30 मिलियन से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
 - उनमें से 4 मिलियन से अधिक मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि **सर्वोच्च न्यायालय के पास 60,000 मामले लंबित** हैं। यह आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है और न्याय प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करता है।
- **वचाराधीन कैदी:** भारतीय जेलों में बंद अधिकांश कैदी वे हैं जो अपने मामलों में नरिणय की प्रतीक्षा कर रहे हैं (यानी वे वचाराधीन कैदी हैं) और उन्हें नरिणयन की अवधितक के लिये बंद रखा जाता है।
 - अधिकांश आरोपितों को जेल में लंबी सज़ा काटनी पड़ती है (दोषी सिद्ध होने पर दी जाने वाली सज़ा की अवधि से अधिक समय तक) और न्यायालय में **स्वयं का बचाव करने से संबद्ध लागत, मानसिक कष्ट एवं पीड़ा वास्तविक दंड की तुलना में अधिक महँगी और पीड़ादायी सिद्ध होती है।**
- **नयुक्त/भरती में देरी:** न्यायिक पदों को आवश्यकतानुसार यथाशीघ्र नहीं भरा जाता है। 135 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 25000 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं।
 - उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या लगभग 400 है और **नचिली न्यायालयों में करीब 35 फीसदी पद खाली पड़े हैं।**
- **CJI की नयुक्ति में पक्षपात और भाई-भतीजावाद:** चूँकि CJI के पद के लिये उम्मीदवारों के मूल्यांकन के संबंध में कोई विशिष्ट मानदंड नहीं हैं, इसलिये इस मामले में भाई-भतीजावाद और पक्षपात आम बात है।
 - परिणामतः **न्यायिक नयुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है और साथ ही वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जिवाबदेह नहीं हैं।**
- **ब्रिटिश शासन से प्रेरित भारतीय न्यायापालिका:** भारत की वर्तमान न्यायिक प्रणाली की उत्पत्ति न्यायापालिका की औपनिवेशिक प्रणाली में देखी जा सकती है जो भारतीय आबादी की आवश्यकताओं के लिये बलिकूल उपयुक्त नहीं है।

आगे की राह

- **नयुक्ति प्रणाली में बदलाव:** रिक्तियों को तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है, और न्यायाधीशों की नयुक्ति के लिये एक उपयुक्त समयसीमा स्थापित करना तथा अग्रिम सुझाव देना आवश्यक है।
 - अन्य महत्त्वपूर्ण कारक जो नरिविवाद रूप से भारत में एक बेहतर न्यायिक प्रणाली विकसित करने में सहायता कर सकता है, वह है **AJIS**।
- **जाँच प्रक्रिया में सुधार:** भारत में एक जाँच संबंधी सक्रिय नीति का अभाव है, जिसके कारण कई नरिदोष लोगों को गलत तरीके से आरोपित किया जाता है और दंडित किया जाता है।
 - इसलिये भारत सरकार को न्याय प्रणाली में सभी हतिधारकों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी, सक्रिय और व्यापक जाँच नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- **न्याय के लिये नवोन्मेषी समाधान:** बड़ी मात्रा में लंबित मामलों के निपटान के समाधान के लिये केवल अधिक न्यायाधीशों की नयुक्ति काफी नहीं है, इसके लिये नवोन्मेषी समाधानों की भी आवश्यकता है।
 - हाल ही में शुरू की गई पहल को एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह समझना आवश्यक है कि न्यायालयों में **इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेज़ी भाषा सभी नागरिकों के समझ में नहीं आती है।**
 - इसे न्याय तक पहुँच तब तक नहीं माना जा सकता जब तक नरिणयों/फैसलों को आम जनता की समझ में आ जाने वाली भाषा में नरिगत नहीं किया जाता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

1. प्रश्न. राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2013)
2. इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है।
3. यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमाँ और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों के लिये दिशा-नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण नमिनलखिति में से कसि प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

1. 1,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति
2. 2,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर
3. अन्य पछिड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्य जनिकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से कम है
4. सभी वरषिठ नागरिक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसि भी सेवानवित्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपतिकी पूर्व अनुमतिसे वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लयि बुलाया जा सकता है ।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा क सर्वोच्च न्यायालय करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयिकुतके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयिकुतआयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । (150 शब्द)

स्रोत: हदिसतान टाइम्स